

श्रमिक शिक्षा क्षेत्रीय केन्द्र 31-12-1972 से बन्द कर दिया गया था क्योंकि उक्त केन्द्र के कार्यकलाप के आधार पर इस बात का औचित्य नहीं रहा था कि उसे उम दिनांक के बाद जारी रखा जाए।

Rise in Price of Coal after Nationalisation of Coking Coal Mines

*796. SHRI SUKHDEO PRASAD VERMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether coal prices have increased after the nationalization of coking coal mines in Bihar ; and

(b) if so, the measures Government propose to take to check the rise in price ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMAR-MANGALAM) : (a) After the taking over of the management of coking coal mines by the Government in October 1971, there has not been any increase in the price of coking coal supplied to [Steel Plants However, it may be clarified that consequent to the decontrol of coal prices with effect from 24.7.1967, it is now entirely for the buyers and settle the prices mutually.

(b) Does not arise.

Leaving of Industrial Relations to Trade Unions

*797. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Hind Mazdoor Sabha President had approached the Government recently for leaving the industrial relations to Trade Unions ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) Recently, the General Secretary of the Hind Mazdoor Sabha proposed to the Government that the present system of third

... arbitration should be replaced by a

(b) This and other related matters are being considered by Government.

कच्छ में प्रवेश करने वाले शरणार्थी

*798. श्री विभूति मिश्र :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या श्रम और पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मोर रिफ्यूजीस क्राम ओवर टू कच्छ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पाकिस्तान में उन पर किए जा रहे अत्याचारों के कारण वे पाकिस्तान से कच्छ आ गए हैं; और

(ग) क्या सरकार उनके भोजन, ठहरने तथा अन्य सुविधाएँ देने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ।

(ख) कहा जाता है कि ये लोग पाकिस्तान में असुरक्षा की परिस्थितियों के कारण यहाँ आए हैं।

(ग) जी, हाँ। शिविरों में रह रहे जरूरत-मंद व्यक्तियों को राहत देने के लिए गुजरात सरकार को पहले ही अधिकार सौंप दिए गए हैं, जिनके अन्तर्गत, निःशुल्क राशन, कपड़े और दैनिक प्रयोग की आवश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए कुछ नकद राशि आती है। इस प्रकार के खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा दी जाएगी।

Supreme Court decision on Section 26 of the Payment of Bonus Act

*799. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court has recently struck down Section 26 of the Pay-